नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 188
दि. 09.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

पीएम मोदी ने 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने' पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

● प्रधानमंत्री ने कम्युनिटी मेडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया

जब न्याय सभी के लिए सुलभ हो, समय पर मिले और किसी व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर नागरिक तक पहुंचे- तभी वह वास्तव में सामाजिक न्याय की नींव बनता है: प्रधानमंत्री

● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है, जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। हाल के वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आगे इस दिशा में प्रयास और तेज किए जाएंगे: प्रधानमंत्री

● मेडिएशन हमारी सभ्यता का एक पुराना हिस्सा रहा है। नया मेडिएशन अधिनियम इसी परंपरा को आधुनिक रूप में आगे बढ़ाता है: प्रधानमंत्री

● आज तकनीक समावेशन और सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरी है। न्याय व्यवस्था में ई कोर्ट परियोजना इस परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है: प्रधानमंत्री

जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं, तो नियमों का पालन बेहतर होता है और मुकदमों की संख्या कम होती है। इसलिए आवश्यक है कि न्यायिक फैसले और कानूनी दस्तावेज स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने" विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होना उनके लिए अत्यंत विशेष है। उन्होंने उल्लेख किया कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत बनाने और विधिक सेवा दिवस से जुड़े कार्यक्रमों से भारत की न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, न्यायपालिका के सदस्यों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों का अभिवादन भी किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, "जब न्याय सभी के लिए सुलभ हो, समय पर हो और हर व्यक्ति तक उसकी सामाजिक या वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पहुंचे, तभी यह सही मायने में सामाजिक न्याय की नींव बनता है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी पहुंच सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर तालुका स्तर तक, विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायपालिका और आम नागरिक के बीच सेतु का काम करते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लोक अदालतों और मुकदमे-पूर्व समझौतों के माध्यम से लाखों विवादों का शीघ्रता से, सौहार्दपूर्ण ढंग से और कम लागत पर समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के तहत केवल तीन वर्षों में लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से देश भर में गरीबों, शोषितों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय में आसानी सुनिश्चित हुई है।

पिछले 11 वर्षों में सरकार द्वारा लगातार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए, श्री मोदी ने बताया कि व्यवसायों के लिए 40,000 से ज्यादा अनावश्यक अनुपालनों को हटा दिया गया है। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से, 3,400 से ज्यादा कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण किया गया है और 1,500 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चले आ रहे कानूनों की जगह अब 'भारतीय न्याय संहिता' ने ले ली है।

प्रधानमंत्री ने दोहराया, "कारोबार में आसानी और जीवनयापन में आसानी तभी संभव है जब न्याय में आसानी भी सुनिश्चित हो। हाल के वर्षों में, न्याय में आसानी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी हम इस दिशा में प्रयासों में तेजी लाएँगे।"

इस वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (ठअछरअ) (नालसा) के 30 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन दशकों में, नालसा ने न्यायपालिका को देश के वंचित नागरिकों से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करने वालों के पास अक्सर संसाधनों, प्रतिनिधित्व और कभी-कभी तो आशा की भी कमी होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा और सहायता प्रदान करना ही "सेवा" शब्द का सही अर्थ है, जो ठअछरअ (नालसा) के नाम में निहित है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ठअछरअ (नालसा) का प्रत्येक सदस्य धैर्य और पेशेवरता के साथ सेवा करता रहेगा।

नालसा के सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल के शुभारंभ की घोषणा करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि यह संवाद और आम सहमति से विवादों को सुलझाने की प्राचीन भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित करता है।

ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक, मध्यस्थता हमेशा से भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग रही है। उन्होंने कहा कि नया मध्यस्थता अधिनियम इस परंपरा को आधुनिक रूप में आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण मॉड्यूल सामुदायिक मध्यस्थता के लिए संसाधन तैयार करने में मदद करेगा, जिससे विवादों को सुलझाने, सद्भाव बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि तकनीक निस्संदेह एक परिवर्तनकारी शक्ति है, लेकिन जब इसका ध्यान जन-हितैषी होता है, तो यह लोकतंत्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, जिससे छोटे से छोटे विक्रेता भी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है, और कुछ ही हफ़्ते पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ लगभग एक लाख मोबाइल टावरों का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि तकनीक अब समावेशिता और सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने ई-कोर्ट परियोजना को एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया कि कैसे तकनीक न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक और मानवीय बना सकती है। उन्होंने बताया कि ई-फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक समन, वर्चुअल सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कदमों ने न्याय प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बना दिया है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि ई कोर्ट परियोजना के

बिहार में एक बार एनडीए की सुशासन, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है : सीएम योगी

बिहार में जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले-यह पाप कांग्रेस और RJD का

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसर चरण के मतदान के लिए रैली की। उन्होंने मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा की। साथ ही कांग्रेस औरआरजेडी पर जमकर हमला बोला।

(जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार ने पहले चरण के मतदान में ही यह संकेत दे दिया है कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाता बिहार चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तो फिर एक बार एनडीए की सुशासन, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है। बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए।

'यह पाप कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों का है'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह वही धरती है जिसने माँ जानकी को शरण दी, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया और जिसने भारत को स्वतंत्रता की दिशा दिखाई। सत्याग्रह की यह भूमि राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र के आग्रह से भी कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि यह धरती नालंदा की ज्ञानगंगा की धारा रही है, आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसी विभूतियों की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि फिर भी बिहार साक्षरता में पिछड़ गया, यह पाप कांग्रेस और आरजेडी की

भूमि संसाधन विभाग ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए विशेष अभियान 5.0 का समापन किया

अक्टूबर 2025 के स्वच्छता अभियान के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा 100 प्रतिशत उपलब्धि और 2,400 फाइल समीक्षाओं के साथ 16 स्वच्छता अभियान चलाए गए

भूमि संसाधन विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के दौरान योग, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला और साइबर सुरक्षा जागरूकता का आयोजन किया।

(जीएनएस)।

सचिव (एलआर) के मार्गदर्शन में, विशेष अभियान 5.0 की प्रगति की बारीकी से निगरानी की गई, जिससे विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गति सुनिश्चित हुई। नोडल अधिकारी और टीम के सदस्यों ने विभाग के रिकॉर्ड रूम सहित सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया।

तेज प्रताप यादव को मिली + सिक्योरिटी, बिहार चुनाव के बीच में लालू के लाल पर गृह मंत्रालय क्यों हुआ मेहरबान

केंद्र सरकार ने जन शक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्हें मोदी सरकार की ओर से वाई प्लस (Y+) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर, अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) तेज प्रताप यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा।

हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को तेज प्रताप यादव की सुरक्षा स्थिति पर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद मंत्रालय ने यह निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में रविवार को जूनागढ से राज्यव्यापी पदयात्रा का प्रारंभ कराएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च - पदयात्रा का आयोजन तथा आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली जाएगी

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 08 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 9 नवंबर रविवार को यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाली राज्यव्यापी पदयात्रा का जूनागढ से प्रारंभ कराएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग तथा जूनागढ जिला प्रशासन के

उपक्रम से इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में 9 नवंबर को जूनागढ नवाबी शासन से स्वतंत्र हुआ था और उसका भारत में विलय हुआ था, जिसे जूनागढ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान से जूनागढ का भारत में विलय कराए जाने के इस यादगार दिवस के समय ही इस वर्ष मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में इस पदयात्रा का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार सुबह 7 बजे इस पदयात्रा का प्रारंभ कराएंगे। इस अवसर पर जूनागढ जिला प्रभारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा, जिला सह प्रभारी विधि राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, जूनागढ के महापौर श्री धर्मेश पोशिया, विधायक तथा पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आचार्य हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज के आठवें 180वें उपवास पारण समारोह को संबोधित किया

● उपराष्ट्रपति ने शांति और वैश्विक मान्यता में जैन धर्म के योगदान पर प्रकाश डाला

● उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य और संस्कृति पर ऐतिहासिक जैन प्रभाव पर प्रकाश डाला

● जड़ों की ओर लौटना: उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल्यों, परिवार और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया

● उपराष्ट्रपति ने भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की

● ज्ञान भारतम मिशन और प्राकृत के लिए शास्त्रीय भाषा मान्यता भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करती है

(जीएनएस)।

श्री हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज जी के आठवें 180 उपवास पारण समारोह में भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए

उपराष्ट्रपति ने दिव्यतपस्वी आचार्य हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज के पवित्र महापर्ण में भाग लेने के लिए बहुत आभार जताया।

दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक, जैन धर्म के गहन योगदान पर रोशनी डालते हुए, श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इसकी शिक्षाओं - अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद - ने भारत और विश्व पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई अहिंसा, वैश्विक शांति आंदोलनों को प्रेरित करती रही है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शाकाहार, पशुओं के प्रति करुणा और सतत जीवन शैली के जैन सिद्धांतों को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के एक आदर्श के रूप में दुनिया भर में मान्यता मिली है।

अपनी व्यक्तिगत यात्रा को याद करते हुए, श्री राधाकृष्णन ने बताया कि उन्होंने 25 वर्ष पहले काशी की यात्रा के बाद शाकाहार अपनाया था, और यह पाया था कि इससे विनम्रता, परिपक्वता और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्राकृत को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देने तथा ज्ञानभारतम मिशन जैसी पहलों के माध्यम से जैन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की।

आईपीएल नीलामी की डेट आई सामने, रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट के लिए सिर्फ इतने दिन बाकी

आईपीएल 2026 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। नीलामी प्रक्रिया दिसंबर में हो सकती है। इससे पहले टीमों को अपने रिटेंशन लिस्ट को जारी करना होगा। रिलीज और रिटेन प्लेयर्स के लिए टीमों की तैयारी चल रही है।

मिनी ऑक्शन की संभावित तारीख 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है। इससे पहले रिटेंशन लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 15 नवंबर है। दैनिक भास्कर ने टीमों के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें कहा गया है कि नीलामी भारत में ही हो सकती है।

महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी खबर यह आई है कि वह अगले सीजन में खेलने वाले हैं। सीईओ काशी विश्वनाथन ने इसकी पुष्टि की है।

लोक सभा अध्यक्ष कोहिमा में सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन-तृतीय के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

नागालैंड के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उप सभापति, नागालैंड विधान सभा के अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे

दो दिवसीय सम्मेलन में प्रतिनिधि 'नीति, प्रगति और लोग:परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल' विषय पर चर्चा करेंगे

(जीएनएस)।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 10 नवंबर 2025 को कोहिमा, नागालैंड में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन-कक्क के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

नागालैंड के मुख्यमंत्री, डॉ. नेफ्यू रियो; राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश; और नागालैंड विधान सभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र जोन-कक्क के अध्यक्ष, श्री शेरिंगैन लोंगकुमेर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

इस दो-दिवसीय सम्मेलन (10-11 नवंबर 2025) में पूरे देश से आए प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है "नीति, प्रगति और लोग: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल"। सम्मेलन के उप-विषय हैं :

(i) विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विधानमंडलों की भूमिका; और

(ii) जलवायु परिवर्तन झ हाल में उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में बादलों के फटने और भूस्खलन के परिप्रेक्ष्य में।

राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश समापन समारोह को संबोधित करेंगे। मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र जोन-कक्क के उपाध्यक्ष श्री थॉमस ए. संगमा तथा नागालैंड विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री एस. तोइहो येप्थो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सम्मेलन के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया जाएगा।

सम्पादकीय

पिछले साल ही चुनावी मैदान में पांव रखने वाले जोहरान ममदानी न्यूयार्क में सबसे युवा मेयर बने

अमेरिका में इस साल यानी 2025 में दो ऐसे चुनाव हुए हैं जिनका असर पूरी दुनिया में पड़ा है। पहला 20 जनवरी को हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दूसरा चुनाव 4 नवम्बर को हुआ जब जोहरान ममदानी ने न्यूयार्व सिटी के मेयर का चुनाव जीता है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं था। कई मामलों में यह ऐतिहासिक चुनाव था। पहली बार 1892 के बाद से न्यूयार्व के सबसे युवा मेयर जोहरान ममदानी की जीत हुई है। वो न्यूयार्व सिटी के पहले मुस्लिम मेयर भी होंगे। उन्होंने पिछले साल ही चुनावी मैदान में पांव रखा था। उस समय उनके पास न तो कोई बड़ी पहचान थी, न ही बहुत सारे पैसे और न ही पार्टी का समर्थन था। यही वजह है कि उनकी एंड्रयू वुओमो और रिपब्लिक उम्मीदवार कार्टिस स्लिवा पर मिली जीत न केवल असाधारण थी पर कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। ममदानी युवा और करिश्माई हैं।

प्री चाइल्ड केयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार और प्री मार्वेट सिस्टम में सरकारी दखल जैसे वामपंथी मुद्दों का समर्थन किया। न्यूयार्व शहर में करीब 48 फीसदी ईसाई और 11 फीसदी यहूदी हैं। यहां मुस्लिम भी नौ फीसदी हैं जो अमेरिका में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। कहा जाता है कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की विरासत से यह शहर अब तक उभर नहीं सका है। यहां आज तक कोई मुस्लिम मेयर रहा भी नहीं।

इसके बावजूद अगर ममदानी को जीत मिली है तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उनकी सुविचारित मुहिम की जीत अधिक लगती है। 34 साल के जिस युवा को उसके कम अनुभव की वजह से पहले चुनावी लड़ाई में कमजोर माना जा रहा था, बाद में वही सबसे अहम पैक्टर साबित हुआ। उनकी खासियत रही जनता से जुड़ाव। उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च करने की बजाए सीधे लोगों से संवाद किया। आम शहरों की समस्याओं को समझा और कई ऐसे वादे किए जो न्यूयार्व के नागरिकों को समझ आ गए, भा गए। ममदानी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी मैनहैटन और न्यूयार्व सिटी के रहने वाले बड़े कापोर्रेट और कारोबारियों की कड़ी आलोचना की थी। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और तमाम उद्योगपतियों ने ममदानी का जमकर विरोध भी किया। ट्रंप ने धमकी भी दे डाली कि अगर ममदानी जीते तो वो उसकी पंडिंग बंद कर देंगे। उनकी मुस्लिम होने पर भी आलोचना की गई पर ममदानी ने खुलकर स्वीकार किया कि वह एक मुसलमान हैं और इस पर उन्हें गर्व है। इसलिए तमाम इस्लामिक दुनिया में उनकी जीत को एक नए युग का आगाज माना जा रहा है। वह न केवल ट्रंप के लिए सिरदर्द बन सकते हैं बल्कि नेतन्याहू को तो अगर वह न्यूयार्व आए तो उन्हें गिरफ्तार करने की भी धमकी वह दे चुके हैं। वह हमारे प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर चुके हैं और 2002 गुजरात दंगों को याद कराते रहते हैं। हालांकि जीतने के बाद अपने पहले भाषण में ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद किया। अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा, मैं जवाहर लाल नेहरू के शब्दों के बारे में सोचता हूं। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

गुजरात आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य

जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट : आदिवासी समुदाय के आनुवंशिक रोगों की पहचान होने से किफायती निदान पद्धति का विकास होगा, 1 लाख रुपए के बजाय केवल 1000-1500 रुपए में होगा परीक्षण

गुजरात की अत्याधुनिक जीनोम सुविधाः 48 से 72 घंटे में होती है 25-50 नमूनों की सीक्वेंसिंग

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध

गांधीनगर, 08 नवंबर (जीएनएस)। गुजरात ने आदिवासी लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2025 को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाने का संकल्प किया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की अस्मिता, आत्मसम्मान और बहादुरी के प्रतीक हैं, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की पहल शुरू की है। श्री मोदी दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि जब हमारे आदिवासी समुदाय समृद्ध होंगे, तो भारत भी समृद्ध होगा। उनके इस विजन का अनुसरण करते हुए गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गुजरात के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप गुजरात, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जीनोम सीक्वेंसिंग (अनुक्रमण) प्रोजेक्ट शुरू किया है।

जीनोम सीक्वेंसिंग और आदिवासी समुदाय के लिए इसका महत्व

शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद आनुवंशिक सामग्री को जीनोम कहा जाता है। कोशिका के अंदर जीन

का सटीक स्थान और उसकी रचना को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। यह जीनोम में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। गुजरात की आदिवासी आबादी लंबे समय से थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रही है। कुछ आनुवंशिक बीमारियां ऐसी होती हैं, जिनके बारे में आखिरी स्टेज तक पता नहीं चल पाता, जिससे उपचार और अधिक जटिल हो जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से वैज्ञानिक म्यूटेशन (परिवर्तनों) का पता लगा सकते हैं, कम लागत वाले डायग्नोस्टिक पैनल बना सकते हैं, और आईवीएफ प्रक्रियाओं के दौरान प्रसवपूर्व या फिर भ्रूण-स्तरीय परीक्षण भी कर सकते हैं।

जीनोम मैपिंग के जरिए आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार का संकल्प

यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों का स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करते हुए बेहतर स्वास्थ्य-उन्मुख योजनाएं बनाने में मदद करेगा। इससे बीमारियों का पता लगाने, कुपोषण और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने तथा सिकल सेल एनीमिया एवं ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज (जी6पीडी) की कमी जैसे आनुवंशिक विकारों का शीघ्र निदान संभव होगा।

उदाहरण के लिए, यदि माता और पिता, दोनों में बीटा-ग्लोबिन जीन (जिसे वाहक कहा जाता है) की एक म्यूटेटेड कॉपी है, तो इस बात की 25 फीसदी संभावना है कि उनके बच्चे को दोनों म्यूटेटेड कॉपियां विरासत में मिलेगी, जिसके चलते सिकल सेल रोग विकसित होगा। जीनोम मैपिंग के माध्यम से ऐसे वाहकों की शीघ्र पहचान की जा सकती है, जिससे रोग के बारे में शीघ्र पता लगाया जा सके और निवारक उपाय किए जा सकें। इससे समुदाय के आनुवंशिक लक्षणों के अनुसार डीएनए परीक्षण तैयार किया जा सकता है।

ये परीक्षण केवल संबंधित समुदाय में आम तौर पर होने वाले जीन परितवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसका खर्च केवल 1000 से 1500 रुपए तक होता है। इसकी तुलना में, संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग व्यक्ति के सभी जीनों की पहचान करता है, जिसमें प्रति नमूना लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होता है और एक्सोम सीक्वेंसिंग केवल जीन के कोडिंग हिस्सों को पढ़ता है, जिसमें प्रति नमूना लगभग 18,000 से 20,000 रुपए का खर्च होता है। इस प्रकार, समुदाय-विशिष्ट परीक्षण ज्यादा व्यावहारिक और कम खचीर्ले होते हैं।

गुजरात जीनोम सीक्वेंसिग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने विशेष आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों के आनुवंशिक खाके (जेनेटिक ब्लूप्रिंट) का अध्ययन करके रोग के परीक्षण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। उल्लेखनीय है कि जीनोम इंडिया पहल के तहत कार्यरत जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों आदिवासी समुदायों में आनुवंशिक विकृतियां बढ़ रही हैं, जो अक्सर अंतर्विवाह (अपने ही समूह में विवाह) और सीमित आनुवंशिक विविधता के कारण होते हैं।

11 जिलों के 31 आदिवासी समुदायों के डीएनए नमूने एकत्र किए जाएंगे

गुजरात में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत शोधकर्ता 11 जिलों के 31 आदिवासी समुदायों में से डीएनए के नमूने एकत्र कर एक डेटाबेस बना रहे हैं, जो इन समूहों में आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार के तरीकों को सुधारने में मदद करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, गुजरात सरकार ने एक व्यापक जीनोम डेटाबेस बनाने और मौजूदा डेटा अंतराल को पाटने के लिए 'आदिवासी आबादी के लिए रेफरेंस जीनोम डेटाबेस का निर्माण' प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के सहयोग से चलाय जा रहा है।

आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए जीनोम विज्ञान का उपयोग करने में गुजरात अग्रणी

गुजरात में जीनोम अनुसंधान को गति देने के लिए जीबीआरसी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें लॉन्ग-रीड सीक्वेंसर सहित तीन जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें शामिल हैं, जो एक समय में 5000-10,000 बेस पेयर (मूल जोड़े) का विश्लेषण कर सकती है, जिससे वैज्ञानिकों को जटिल आनुवंशिक बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है। इन मशीनों का उपयोग पहले कोविड-19 के दौरान किया जाता था, लेकिन अब इनका उपयोग व्यापक जीनोम अनुसंधान के लिए किया जा रहा है।

गुजरात में, प्रत्येक सीक्वेंसिंग बैच 25-50 मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकता है, इसके परिणाम 48 से 72 घंटे में तैयार हो जाते हैं। जीबीआरसी ने लागत प्रबंधन और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके प्रति नमूना खर्च 85,000 रुपए से घटाकर लगभग 60,000 रुपए कर दिया है। यह अनुसंधान डॉक्टरों को सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी उपचार प्रदान करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आदिवासी समुदाय को आधुनिक जीनोम विज्ञान का लाभ मिले।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस : भारत की विधिक सहायता एवं जागरूकता पहल

9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना हुई।

(जीएनएस)। मुख्य बातें

भारत की कानूनी सहायता प्रणाली 44.22 लाख लोगों (2022-25) तक पहुंच चुकी है और लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ मामलों का समाधान किया गया है।

2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का समाधान किया गया।

लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फरवरी, 2025 तक) को दिशा योजना के माध्यम से मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क सेवाएं और कानूनी प्रतिनिधित्व एवं जागरूकता प्रदान की गई।

परिचय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा की गारंटी देता है। फिर भी, कई लोग अशिक्षा, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं, अपराध या आर्थिक तंगी व अन्य बाधाओं के कारण कानूनी सेवाओं तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। चूंकि यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था, इसलिए इसके कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं की उपलब्धता के क्रम में, इस दिन, देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरणों के अलावा, फास्ट-ट्रैक और अन्य विशेष अदालतें अदालती मामलों में तेजी लाने में मदद करती हैं, वहीं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण पहल और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय को अधिक सुलभ और सस्ता बनाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने यह सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विधिक सहायता संगठनों की स्थापना की कि आर्थिक या अन्य बाधाओं से जूझ रहे किसी भी नागरिक को न्याय पाने के समान अवसर से वंचित न किया जाए।

इस अधिनियम ने निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित कीः

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

अ कानूनी सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित की जाती है और तीन-स्तरीय वित्त पोषण संरचना के माध्यम से अनुदान दिया जाता है:

राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण को केंद्रीय वित्त पोषण या दान

राज्य कानूनी सहायता कोष के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को केंद्र या राज्य सरकार का वित्त पोषण या अन्य योगदान

जिला कानूनी सहायता कोष के माध्यम से जिला प्राधिकरण को राज्य सरकार का वित्त पोषण या अन्य दान

पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दी गई कानूनी सहायता और सलाह से 44.22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

लोक अदालत

इस अधिनियम ने लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की, जो उपरोक्त विधिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित वैकल्पिक विवाद निवारण मंच हैं। ये मंच लंबित विवादों या मामलों या मुकदमे-पूर्व चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करते हैं। 2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना

एनएएलएसए द्वारा शुरू की गई एलएडीसीएस योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी बचाव प्रदान करती है।

30 सितंबर, 2025 तक, 668 जिलों में एक कार्यशील एलएडीसीएस कार्यालय है।

2023-24 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) तक एलएडीसी द्वारा सौंपे गए 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए एलएडीसी योजना का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये है।[11]

न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना

आधुनिक तकनीक लोगों को न्याय व्यवस्था तक आसानी से और किफायती पहुंच बनाने में भी मदद कर रही है। 2021-2026 तक लागू की गई दिशा योजना के माध्यम से लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फरवरी, 2025 तक) को मुकदमेबाजी से पहले सलाह, निःशुल्क सेवाएं, और कानूनी प्रतिनिधित्व व जागरूकता प्रदान की गई। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका परिव्यय 250 करोड़ रुपये है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

बहुत से लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं। नालसा बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों और समाज के अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित कानूनों पर विभिन्न कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

अधिकारी सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने इनमें भाग लिया।

न्याय विभाग, दिशा के अंतर्गत कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (छछछअढ) चलाता है। सिक्किम राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रछरअ) जैसी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियाँ इस कार्यक्रम का संचालन करती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं और बोलियों में संचार सामग्री विकसित की है।

दूरदर्शन ने भी मंत्रालय के साथ सहयोग किया और छह भाषाओं में 56 कानूनी जागरूकता टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनकी पहुंच 70.70 लाख से ज्यादा लोगों तक हुई। 2021 से 2025 तक सरकारी सोशल मीडिया चैनलों पर सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर 21 वेबिनार प्रसारित किए गए। कुल मिलाकर, एलएलएलएपी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुँचा।.

फास्ट ट्रैक और अन्य न्यायालय

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पांच साल से ज्यादा समय से लंबित संपत्ति मामलों से संबंधित जघन्य अपराधों और दीवानी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) स्थापित किए गए थे-जहां 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के दौरान 1,800 एफटीसी की सिफारिश की थी, वहीं 30 जून, 2025 तक 865 एफटीसी कार्यरत हैं।

अक्टूबर 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना ने गंभीर यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना की, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम के तहत पीड़ित भी शामिल हैं; 30 जून 2025 तक, 392 विशेष ढडउरड अदालतों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक हैं और स्थापना के बाद से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है।

2019-20 में 767.25 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 474 करोड़ रुपये) के प्रारंभिक आवंटन के साथ शुरू हुई यह योजना दो बार बढ़ाई जा चुकी है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च, 2026 तक है, जिसमें 1,952.23 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 1,207.24 करोड़ रुपये) का परिव्यय है।

अन्य न्यायालय

ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर की अदालतें हैं। मार्च 2025 तक, 488 ग्राम न्यायालय हैं, जो ग्रामीणों को समय पर, किफायती और कुशल न्याय तक पहुँच प्रदान करते हैं। ये जमीनी स्तर की अदालतें विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती हैं।

नारी अदालतें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इन अदालतों का उद्देश्य घरेलू हिंसा और अन्य लिंग-आधारित हिंसा से संबंधित मुद्दों को आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से सुलझाना है।

इन अदालतों का नेतृत्व 7-9 महिलाएं करती हैं और ये महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें कानूनी सहायता और अन्य सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का काम करती हैं।

नारी अदालत असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है।

इसका पायलट परीक्षण किया जा रहा हैः

16 राज्यों अर्थात गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 10-10 ग्राम पंचायतें; और

2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5-5 ग्राम पंचायतें।

पाकिस्तान ने 33 सालों बाद बनाया धांसू रिकॉर्ड, दक्षिण अफ्रीका के सामने रचा इतिहास

(जीएनएस)।

कराची में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। युवा बल्लेबाज सैम अय्यूब ने शानदार अर्धशतक जमाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 37.5 ओवर में महज 143 रन पर ढेर हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने 53 रन (70 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का) की पारी खेली और टीम को संभालने की कोशिश की। वहीं, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने 39

रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका।

पाकिस्तान की ओर से अबफ्फ़ाफ अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेट मिले। लक्ष्य छोटा था और पाकिस्तान ने इसे आसानी से हासिल कर लिया।

जवाबी पारी में सलामी बल्लेबाज फखर जमान बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन सैम अय्यूब ने शुरूआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने 77 रन (70 गेंद, 11 चौके, 1 छक्का) की आतिशी पारी खेली और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया।

बाबर आजम ने 27 रन जोड़े, जबकि विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाबाद लौटे। पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में ही 144 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से नांद्रे बर्गर और ब्योर्न फॉर्च्यून ने एक-एक विकेट लिया, लेकिन वे पाकिस्तान की बल्लेबाजी को रोक नहीं सके।

पाकिस्तान ने अपने घरेलू मैदान पर पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछले पांच वनडे सीरीज में से चार में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अबरार अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच और क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

'सैयां नहीं तो भैया', सलमान खान ने सरेआम तान्या मित्तल को किया एक्सपोज

(जीएनएस)।

टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी 'वीकेंड का वार' एपिसोड दर्शकों के लिए रोमांच और ड्रामा से भरपूर रहने वाला है। होस्ट सलमान खान ने इस बार कई प्रतियोगियों की क्लास लगाई, जिनमें तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे नाम शामिल हैं।

तान्या मित्तल के गेम प्लान का खुलासा

हाल ही में जारी प्रोमो वीडियो में सलमान खान तान्या मित्तल के गेम स्ट्रैटेजी का पदार्फाश करते दिखे। सलमान ने तान्या से कहा, "आपने जो नॉमिनेशन प्लान बनाया था, वो तो बिग बॉस ने ही बेकार कर दिया। आपने कहा था कि अमाल को 'भैया' बोलूंगी, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा।" इसके बाद सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अब भैया से सैंया पर तो जा नहीं सकते। अगर यही आपका गेम प्लान था, तो वाह क्या गेम प्लान है आपका।" सलमान की यह बात सुनकर तान्या मित्तल चुप

रह गईं और उनके चेहरे के हावभाव बदल गए।

अमाल मलिक से दूरी पर भी उठे सवाल

दरअसल, शो में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच पिछले कुछ समय से टकराव चल रहा है। हालांकि, जब ड्यूटीज बांटने का समय आया तो उन्होंने अमाल को 'भैया' कहकर संबोधित किया, जिससे घरवालों और दर्शकों दोनों का ध्यान उनकी ओर गया।

फरहाना और नीलम पर भी बरसे सलमान

तान्या के अलावा सलमान खान ने इस एपिसोड में फरहाना भट्ट और नीलम गिरी की भी जमकर क्लास लगाई सलमान ने दोनों से उनके व्यवहार और बयानों पर सवाल पूछे, जिससे माहौल और भी गरम हो गया।

दर्शकों में बढ़ी उत्सुकता

'वीकेंड का वार' का यह एपिसोड सोशल मीडिया पर रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है। फैंस यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि सलमान खान आगे किन कंटेस्टेंट्स की पोल खोलने वाले हैं। एक बात तो तय है - इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' ड्रामा, हंसी और एक्सपोजर का पूरा पैकेज साबित होने वाला है। तान्या ने घर में कई बार अमाल को नजरअंदाज किया और उनकी बातों का जवाब देने से भी इंकार कर दिया।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के विश्वामित्री झ डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 09 नवम्बर 2025 से 13 नवम्बर 2025 तक कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार है:

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1.ट्रेन नं 69202 एकतानगर झ प्रतापनगर मेमू ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

2.ट्रेन नं 69203 प्रतापनगर – एकतानगर मेमू ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

3.ट्रेन नं 59122 छोटाउदैपुर – प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

4.ट्रेन नं 59125 प्रतापनगर झ छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर परा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु कैटरिंग स्टॉल का शुभारंभ

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत आने वाले भावनगर परा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैटरिंग स्टॉल का शुभारंभ दिनांक 08 नवम्बर, 2025 को किया गया।

इस स्टॉल का उद्घाटन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव श्री एस. के. श्रीवास्तव, मंडल वाणिज्य निरीक्षक श्री तुषार शेख, मंडल परिचालन निरीक्षक श्री संजय सिंह, स्टेशन अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार, रेलवे कर्मचारीगण एवं रेल यात्री उपस्थित रहे।

उद्घाटन अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कैटरिंग स्टॉल के लाइसेंसी श्री विकास कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने श्री विकास कुमार को प्रोत्साहित करते हुए स्टॉल से खरीददारी भी की। उपस्थित अन्य कर्मचारियों एवं यात्रियों ने भी स्टॉल से खाने-पीने की वस्तुएं क्रय कर स्थानीय स्तर पर शुरू की गई इस सुविधा की सराहना की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस स्टॉल के खुलने से भावनगर परा स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वच्छ, ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित दरों पर प्राप्त होगी, जिससे यात्री सुविधाओं में और अधिक वृद्धि होगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा की भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशनों पर विभिन्न सेवाओं के विस्तार की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।

सीएक्यूएम ने 2025 में धान कटाई मौसम के दौरान पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए हरियाणा एवं पंजाब द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की

आयोग ने पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल एवं समन्वित कार्रवाई का आ'ान किया

हरियाणा में प्रोत्साहन योजनाओं, प्रवर्तन एवं जमीनी स्तर पर मध्यवर्तन से पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है

(जीएनएस)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने श्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब का क्षेत्रीय दौरा किया जिसका उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से फसल अवशेष प्रबंधन एवं प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित जमीनी स्थिति का आकलन करना था।

आयोग ने पटियाला जिले के राजपुरा में ताप विद्युत संयंत्र, संगरूर जिले के लहरागागा में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र, मशीनरी के माध्यम से पराली का जमीनी स्तर पर प्रबंधन और बठिंडा जिले के लहरा मोहब्बत में ताप विद्युत संयंत्र का निरीक्षण किया। अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने लहरा मोहब्बत ताप विद्युत संयंत्र का निरीक्षण करते हुए इसकी खराब परिचालन स्थिति तथा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों एवं वायु गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सीएक्यूएम अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर इनमें सुधार लाने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए गए तो आयोग संयंत्र को बंद करने का निर्देश जारी करने के लिए बाध्य हो सकता है। निरीक्षण के दौरान, टीम के सामने पराली जलाने की छिटपुट घटनाएं सामने आयी।

दौरा पूरा करने के बाद, आयोग ने 07 नवंबर 2025 को पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई का अवलोकन किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान आयोग को पता चला कि 15 सितंबर से 06 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान पंजाब में पराली जलाने के 3,284 मामले दर्ज किये गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 5,041 मामले दर्ज किये गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार को दशार्ता है। मुक्तसर और फाजिल्का जैसे कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जो चिंता का विषय है और इसमें राज्य को तत्काल मध्यवर्तन करने की आवश्यकता है। आयोग ने पाया कि पंजाब में सितंबर 2025 तक, चार ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) (पीएसपीसीएल के 2 टीपीपी: लेहरा और रोपड़; टीएसपीएल- मानसा और एनपीएल- एलएंडटी) ने कुल मिलाकर केवल 3.12 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष का ही सह-प्रज्वलन किया, जबकि 2025-26 के लिए 11.83 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

आयोग ने कहा कि पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पंजाब में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अध्यक्ष ने पंजाब को आयोग के निदेर्शों का पालन करने के लिए तुरंत अपने प्रयास में तेजी लाने और एक सशक्त सूचना एवं संचार अभियान चलाने का निर्देश दिया। आयोग ने धान की पराली के उपयोग हेतु फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने और धान की पराली का उपयोग करने वाले संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों और अन्य उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। आयोग ने जमीनी स्तर पर बेहतर प्रवर्तन एवं जवाबदेही तंत्र पर भी बल दिया। आयोग ने उन नोडल अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जिनके अंतर्गत आने वाले खेतों में आग लगने की ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

इसके अलावा, हरियाणा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन करते हुए, आयोग ने 07 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक भी की। बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 15 सितंबर से 06 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, हरियाणा में पराली जलाने की 206 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान 888 मामले दर्ज हुए थे। मामलों में हुई कमी सक्रिय, प्रोत्साहन-आधारित एवं प्रवर्तन-संचालित दृष्टिकोण का परिणाम है। इसके अलावा, सीएक्यूएम ने कहा कि फसल अवशेषों के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए किसानों को दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों से उनके व्यवहार में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि समन्वित प्रयासों से खेतों में आग लगने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।

आयोग ने हरियाणा में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अन्य प्रमुख क्षेत्रों की भी समीक्षा की, जिनमें वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक स्रोत, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न धूल, सड़क की धूल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन आदि शामिल हैं तथा इन स्रोतों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयोग ने क्षेत्र में स्थायी फसल अवशेष प्रबंधन एवं स्वच्छ वायु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय, कार्य योजनाओं का सही कार्यान्वयन एवं आयोग द्वारा जारी वैधानिक निदेर्शों को सख्ती से लागू करने के महत्व को दोहराया।

वाणिज्य विभाग ने दक्षता और स्वच्छ शासन के लिए विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्य कुशलता में सुधार लाना और विभाग, उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और संबद्ध संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना था। इस पहल के माध्यम से, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और कार्यस्थल प्रबंधन एवं स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए।

विभाग के नोडल अधिकारी और उसके क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विशेष अभियान 5.0 की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी गई, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर गति सुनिश्चित हुई। विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों एवं संगठनों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अभियान के दौरान, 88,385 फाइलों की समीक्षा की गई और 46,255 फाइलों को हटाया गया। कुल 277 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिनसे ई-कचरे और स्क्रैप के निपटान से लगभग 70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, और इसके परिणामस्वरूप 36,005 वर्ग फुट कार्यालय स्थान भी मुक्त हुआ।

अभियान के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में मुंबई स्थित भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) मुख्यालय में व्यापक स्तर पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना; छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ लगाना और शून्य कार्बन जोन का निर्माण; हरियाली विकास, बेहतर पार्किंग सुविधाओं और स्थान अनुकूलन के माध्यम से कार्यालय परिसर का संवर्धन; और मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एमईपीजेड) परिसर के पास झील का पुनरुद्धार शामिल था। अन्य पहलों में डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन, ई-कचरे पर जागरूकता

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न

दोनों पक्षों ने शीघ्र, संतुलित और व्यापक व्यापार समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की

(जीएनएस)।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चौथे दौर की वार्ता आज ऑकलैंड और रोटोरुआ में संपन्न हुई। दोनों पक्षों के बीच पांच दिनों तक रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चा हुई।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री श्री टॉड मैक्ले ने इस दौर में हुई स्थिर प्रगति की सराहना की और एक आधुनिक, व्यापक और भविष्योन्मुखी एफटीए की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग और उत्पत्ति के नियमों सहित प्रमुख क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा की। इन चचाओं में आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने की साझा महत्वाकांक्षा परिलक्षित हुई जो लचीले, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत वैश्विक समृद्धि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देने वाली गहरी आर्थिक साझेदारियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से व्यापार प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि, निवेश संबंधों में गहनता, आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता और दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बेहतर पूवार्नुमान और बाजार पहुँच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

डिजीलॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ने वाली ट्रस्ट लेयर के रूप में काम करता है - जो सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और जवाबदेह डिजिटल गवर्नेंस को सक्षम बनाता है: एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NeGD ने 'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया; सम्मेलन में डिजिटल ट्रस्ट और दक्षता की आधारशिला के रूप में डिजीलॉकर की भूमिका को दिखाया गया

सात राज्यों को 'डिजीलॉकर एक्सीलरेटर' के रूप में मान्यता दी गई - असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया

राज्यों और उद्योग भागीदारों ने शासन, शिक्षा और वित्त में डिजीलॉकर के स्केलेबल उपयोग-मामलों को प्रदर्शित किया

(जीएनएस)।

इस सप्ताह नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजीलॉकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका विषय था – 'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना'। इस सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में पेपरलेस गवर्नेंस, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में डिजीलॉकर की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल दिया गया, जो देश में हो रही डिजिटल ट्रस्ट क्रांति में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (ठीॠक्ष) ने भारत मंडपम में इसका आयोजन किया। इस सम्मेलन ने सहयोगी मंच प्रदान किया ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके और दिखाया जा सके कि डिजीलॉकर कैसे एक साधारण सुरक्षित दस्तावेज भंडारण सुविधा से सरकार, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों में विश्वास, सुविधा और दक्षता की आधारशिला के रूप में विकसित हो रहा है।

एनएचपीसी ने मनाया 51वाँ स्थापना दिवस

(जीएनएस)।

सरकार का एक "नवरत्न" उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड ने 7 नवंबर 2025 को अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने और अपने 51वें स्थापना दिवस का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। एनएचपीसी के फरीदाबाद स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विधुत स्टेशनों और परियोजनाओं में भव्य समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारतीय डाक द्वारा एनएचपीसी पर जारी "कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प" का विमोचन किया। मुख्य अतिथि ने एनएचपीसी की गौरवशाली 50 वर्षों की यात्रा और प्रमुख उपलब्धियों को दशार्ती "उपलब्धि पुस्तिका" का भी विमोचन किया।

एनएचपीसी के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में आयोजित समारोह में दीप प्र ज्वलित करने के बाद मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सचिन किशोर, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता, एनएचपीसी के निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी और स्वतंत्र निदेशकगण शामिल थे।

इससे पहले माननीय केंद्रीय विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सचिन किशोर का एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता ने पौधा और शॉल भेंट कर स्वागत किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सचिन किशोर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) श्री उत्तम लाल, निदेशक (परियोजनाएं) श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) श्री सुप्रकाश अधिकारी, निदेशक (वित्त) श्री महेश शर्मा, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री संतोष कुमार और एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

इस समारोह में विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों/विभागों के प्रतिनिधि, एनएचपीसी के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

एनएचपीसी की स्थापना के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने एनएचपीसी के 12 प्रतिष्ठित बांधों और बैराजों को दशार्ते हुए एक कस्टमाइज्ड "माई स्टैम्प" जारी किया। ये संरचनाएँ इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के उल्लेखनीय उदाहरण हैं और राष्ट्र के लिए जलविद्युत के दोहन में एनएचपीसी की विशेषज्ञता का प्रतीक हैं।

पिछले 50 वर्षों में एनएचपीसी की उपलब्धियों को दशार्ती उपलब्धि पुस्तिका, आकर्षक तस्वीरों के माध्यम से संगठन के समृद्ध इतिहास, उल्लेखनीय उपलब्धियों, तकनीकी उत्कृष्टता और 1975 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण के प्रति पाँच दशकों की अटूट प्रतिबद्धता को खूबसूरती से दशार्ती है।

माननीय मुख्य अतिथि ने समारोह को संबोधित करते हुए एनएचपीसी को उसके 51वें स्थापना दिवस और उसकी स्वर्णिम यात्रा के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपनी उल्लेखनीय प्रगति के पाँच दशकों के दौरान, जलविद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी का असाधारण योगदान पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने का आ'ान किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एनएचपीसी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए एनएचपीसी को अपनी विद्युत उत्पादन प्रक्रियाओं में नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना होगा और तकनीकी नवाचारों को अपनाना होगा।

"भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के सहयोग से "भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का 6 और 7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में आयोजन किया

विकसित भारत 2047 के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने हेतु उपचारित जल की क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया

उपयोग को बढ़ाने के लिए समान मानकों को अपनाने पर सहमति बनी

शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में उपचारित जल के दोबारा इस्तेमाल को अपनाने की जरुरत पर बल दिया गया

डेटा सेंटर जैसी उभरती जरुरतों को पूरा करने के लिए उपचारित जल के उपयोग का सुझाव दिया गया

(जीएनएस)।

नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के सहयोग से ,अपने राज्य सहायता मिशन के तहत 6-7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में 'भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती (डॉ.) शालिनी रजनीश और 18 राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें थिंक टैंक, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, यूनिसेफ, दक्षिण भारत के लिए इजराइल सरकार के प्रतिनिधि, सिंगापुर जल संघ और ज्ञान साझेदारों के नीति विशेषज्ञों ने भाग लिया, ताकि कृषि, घरेलू गैर-पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए उपचारित जल के उपयोग को बढ़ाने में चुनौतियों, अवसरों और नवाचारों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

उभरते मीठे पानी के संकट के संदर्भ में, डॉ. पॉल ने विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतर दृष्टिकोणके लिए प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने की जरुरत पर बल दिया, पुनः उपयोग पर राज्य स्तरीय नीतियों की जरुरत और विभिन्न उपयोगों के लिए लागू करने योग्य सामान्य मानक विकसित करने, डेटा सेंटर जैसे उभरते जल आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग को एकीकृत करने, पुनः उपयोग के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं और व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने से, जल सुरक्षा बेहतर करने, मीठे पानी पर निर्भरता कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और संसाधन चक्रीयता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक बदलावकारी मौका मिलता है। उन्होंने उपचारित जल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव ने शहर में 2024 की संकटकालीन स्थिति में राज्य द्वारा की गई अग्रणी पहलों का उल्लेख किया, जैसे झीलों के पुनरुद्धार के लिए प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग और औद्योगिक माँग को पूरा करना। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से देश और राज्य के लिए रणनीतिक विचारों के साथ आगे आने की अपील की, ताकि पुनः उपयोग क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें।

कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने 2030 तक मजबूत राज्य-स्तरीय नीतियों और बहु-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए स्पष्ट साझा मानकों की जरुरतों पर जोर दिया। इसके अलावा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड अवसंरचना और उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य के नजरिए से वास्तविक समय गुणवत्ता निगरानी प्रणालियाँ और उपयोगिताओं के भीतर क्षमता निर्माण की स्थापना के महत्व पर भी जोर दिया गया। विकेन्द्रीकृत उपचार प्रणालियों के लिए लागत-प्रभावी तकनीकों और टिकाऊ संचालन तथा रखरखाव ढाँचों की जरुरत को उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए ठोस कारकों के रूप में पहचाना गया।

इस दौरान वरिष्ठ राज्य पदाधिकारियों द्वारा कई राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी पेश किया गया। गुजरात के स्केलेबल पुनः उपयोग मॉडल, दिल्ली की राजस्व-उत्पादक पहल, पुनः उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए इंदौर का बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, कर्नाटक की एकीकृत ग्रामीण-औद्योगिक पुनः उपयोग प्रणालियाँ, औद्योगिक उपयोग के लिए तमिलनाडु का तृतीयक उपचारित जल और महाराष्ट्र के प्रौद्योगिकी-सक्षम ग्रे वाटर समाधान, ये सभी अन्य राज्यों के लिए पुनः उपयोग को बढ़ाने की संभावनाएँ प्रदान करते हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण साझा किए गए, जिनमें भारत की एक वृत्ताकार जल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को रफ्तार देने के लिए सहयोगी व्यावसायिक मॉडल, नवोन्मेषी वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

कार्यशाला का समापन 7 नवंबर को बीडब्ल्यूएसएसबी के केएंडसी वैली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कब्बन पार्क ट्रीटमेंट प्लांट के क्षेत्रीय दौरे के साथ हुआ, जहाँ राज्यों के प्रतिभागियों ने उपचार और पुनः उपयोग की उन्नत तकनीकों का अवलोकन किया।

कर्नाटक के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तुषार गिरि नाथ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अमृत विभाग की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक श्रीमती डी. थारा, ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम के मुख्य आयुक्त श्री महेश्वर राव, नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री युगल जोशी और बेंगलुरु जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वी. राम प्रसाद मनोहर ने कार्यशाला में विचार-विमर्श में भाग लिया।

बकरा चोरी कर भाग रहे दो चोरः बालिका की सूझबूझ से ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस

(जीएनएस)।

पीलीभीत के सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के बरगदिया गांव में शुक्रवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब दो बाइक सवार युवक घर के बाहर बंधा एक बकरा चोरी कर ले गए। एक बालिका की सूझबूझ और ग्रामीणों की बहादुरी से चोरों को भीरा जंगल के पास पीछा कर पकड़ लिया गया।

यह घटना गांव निवासी शहाबुद्दीन के घर के बाहर हुई। घर के सदस्य नमाज पढ़ने गए हुए थे, तभी दो युवक बाइक से आए और मौका पाकर बकरा खोलकर फरार हो गए।

पड़ोस में रहने वाली एक बालिका ने चोरी की यह घटना देख ली और तुरंत शोर मचाया। बालिका की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और बाइक सवार चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक पीछा करते हुए दोनों चोरों को भीरा जंगल के पास पकड़ लिया।

चोरों को पकड़ने के बाद ग्रामीण उन्हें वापस गांव ले आए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पकड़े गए दोनों चोरों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि दो व्यक्ति बकरा चुराकर ले जा रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ा। पुलिस अब पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

सदर कोतवाली में युवती लापताः दूसरे समुदाय का युवक बहला-फुसलाकर ले गया,मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज

(जीएनएस)।

पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां 20 वर्षीय एक युवती को दूसरे समुदाय का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और युवती को सकुशल बरामद करने के लिए संयुक्त टीमें लगाई हैं।

तहरीर के अनुसार, आरोपी युवक हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर सर्वा का निवासी है। घटना 3 नवंबर की सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। युवती की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनकी बेटी से लंबे समय से फोन पर संपर्क में था। दोनों की पहचान पिछले साल शहर में लगे एक मेले के दौरान हुई थी। मेले में आरोपी ने आइसक्रीम की दुकान लगाई थी, जहां युवती भी पहुंची। वहां

बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई और बाद में प्रेम-प्रसंग का रूप ले लिया। मां का कहना है कि युवक ने झूठे वादे कर बेटी को भटकाया और रात के अंधेरे में घर से ले गया।

परिवार ने जैसे ही युवती के लापता होने का पता लगाया, तुरंत सदर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया, "तहरीर मिलते ही आरोपी के खिलाफ क्ढउ की धारा 363 (अपहरण), 366 (बहला-फुसलाकर ले जाना) और अन्य संबंधित धाराओं में ऋऋकदर्ज कर ली गई है। आरोपी के हर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। युवती की उम्र को देखते हुए मामला संवेदनशील है, इसलिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वह सकुशल वापस लौट आए।" पुलिस ने आरोपी के फोन लोकेशन व परिजनों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।

यह घटना इलाके में सामुदायिक सद्भाव और युवतियों की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया जाएगा। अगर कोई जानकारी हो, तो तुरंत 112 पर कॉल करें।

डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 10वीं सब जूनियर प्रदेशीय तीरंदाजी प्रतियोगिता

(जीएनएस)।

बाराबंकी। डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 10वीं सब जूनियर प्रदेशीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। ज्ञात हो कि नगर के के.डी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश वर्मा कर्रा ने विजयी खिलाड़ियों एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालक वर्ग से बागपत के अंश शेखावत ने प्रथम, सोनभद्र के प्रियांशु ने द्वितीय, बागपत के लव ने तृतीय स्थान मिला। वहीं बालिका वर्ग से बागपत की वेदाक्षी तोमर ने प्रथम,

कानपुर नगर की रत्नाम दीक्षित ने द्वितीय व मुजफ्फरनगर की दिव्यांशी ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 450 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि राकेश वर्मा कर्रा ने कहा कि भाजपा सरकार खेल के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास लगातार कर रही हैं। धनुर्विद्या प्राचीन काल से हमारे बीच चली आ रही है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे धर्मग्रन्थों व पुराणों आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाराबंकी जिले में आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन होना अपने आप में एक गौरव का विषय है। साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएँ भी दी। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश सोनकर, जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हरपाल सिंह, कोषाध्यक्ष अश्वनी वर्मा, बलराम कृष्ण यादव, अभिषेक पटेल, कपिल वर्मा, योगेंद्र सिंह राणा आदि कई लोग उपस्थित रहे।

अतरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम मधुमिता सिंह ने मसौली क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत शनिवार को अतरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम मधुमिता सिंह ने मसौली क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया। बीएलओ से फॉर्म वितरण और संकलन की स्थिति की जानकारी ली।

अतरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम मधुमिता सिंह ने ग्राम नयागाँव, करपिया, नेवला करसंडा, बड़ागांव, मसौली के बूथों पर जाकर चल रहे एसआईआर कार्य प्रगति की जानकारी ली तथा सभी बीएलओ से कहा कि सभी प्रपत्र समय से भरवाकर जमा कराएं। उन्होंने सभी मतदाताओं से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की, ताकि वोटर लिस्ट को सही ढंग से तैयार किया जा सके। उन्होंने प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुद्धता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान अपने मतदेय स्थल के समस्त मतदाताओं से सम्पर्क करते हुए प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र

दो प्रतियों में उपलब्ध कराए और उन्हें गणना प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान की जायेगी। बीएलओ द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन एवं अन्य अशक्त समूहों के मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त करने एवं भर कर जमा करने में कोई असुविधा न हो और कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान सूची से वंचित न रहे। इस दौरान अतरिक्त मजिस्ट्रेट मधुमिता सिंह ने पंचायत भवन बड़ागांव मे संचालित लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और बच्चो से मन लगाकर पढ़ने की अपील की।

वीणा सुधाकर महाविद्यालय चल रही दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। वीणा सुधाकर महाविद्यालय मसौली में चल रही दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता मे प्रतिभागी बच्चो को महाविद्यालय के प्रबंधक मयंक ओझा एव पूर्व ब्लाक प्रमुख रामनगर राजन ने बच्चो को मैडल देकर सम्मानित किया।

दो दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में महाविद्यालय के बालक एवं बालिका वर्ग के विद्यार्थियों ने लांग जंप, कबड्डी, वॉलीबॉल, भाला फेंक, खो-खो, चक्का फेंक, गोला फेंक प्रतियोगिता मे शामिल हुए जिसमे बालक वर्ग की सौ मीटर दौड़ मे आकाश यादव प्रथम राज गुप्ता द्वितीय व आनंद कुमार तीसरे स्थान पर रहे बालिका वर्ग की दौड़ मे वीनू मौर्या प्रथम आकृति राजवंशी द्वितीय एव

शिवानी तीसरे स्थान पर रही। चार सौ मीटर दौड़ मे आकाश यादव प्रथम शैलेन्द्र कुमार द्वितीय व आनंद कुमार तीसरे स्थान पर रहे बालिका वर्ग की दौड़ मे हिना प्रथम सपना द्वितीय व कशिश तीसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता मे आकाश वर्मा की टीम विजेता व मोहम्मद कैफ की टीम उपविजेता रही। बालिका वर्ग कि

कबड्डी प्रतियोगिता मे हिना की

टीम विजेता व उजमा बानी की टीम उपविजेता रही। बालक वर्ग की लंबी कूद मे विवेक यादव प्रथम राज गुप्ता द्वितीय शिवम कुमार तृतीय,

भाला फेंक प्रतियोगिता बालिका वर्ग मे संजना प्रथम बबीता द्वितीय व छाया तृतीय, बालक वर्ग गोला फेंक प्रतियोगिता मे आशीष प्रथम शैलेंद्र द्वितीय नमन तृतीय

गोला फेंक बालिका वर्ग मे संध्या पाल को प्रथम नंदनी राजपूत द्वितीय निशा तीसरे स्थान पर रही।

प्रतियोगिता का समापन के बाद प्रबंधक मयंक ओझा एव शैक्षिक समन्वयक डॉ दिनेश कुमार सिंह द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों को मेडल एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर राजन सिंह ने बच्चो का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल हमारे देश के प्राचीनतम खेल है जिसकी देश में बड़ी पहचान है ।ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम प्रतिभायें मौजूद हैं जिनमे निखार लाने के लिए ऐसे खेलो का आयोजन विशेष महत्व रखता है। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी सफलता में गुरु का विशेष योगदान रहता है आप सभी लोगो पर बच्चों को प्रतिभावान बनाने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रगान के साथ दो दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन किया गया।

खेल प्रभारी एवं भूगोल विभागाध्यक्ष गुलाम नवी की निगरानी विष्णु मिश्रा का विशेष योगदान रहा। अमरजीत कनौजिया, जितेंद्र यादव, जीशान अहमद, आराधना वर्मा, डॉ. अर्चना सिंह, सरिता सिंह, चंद्र मोहन तिवारी तथा तकनीकी टीम से सौरभ सिंह एवं प्रदीप उपस्थित रहे।

महादेवा महोत्सव की तैयारियों का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा

समय से पूरी हों व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं को न हो कोई असुविधा – गुंजिता अग्रवाल

(जीएनएस)।

रामनगर (बाराबंकी)। तहसील रामनगर के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री लोधेश्वर महादेवा धाम में होने वाले महादेवा महोत्सव की तैयारियों का शनिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने महोत्सव पंडाल की भूमि, झूला, स्टाल, बालीवाल तथा सभी मार्गों का गहनता से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महोत्सव से जुड़ी सभी तैयारियां तय समय सीमा में पूरी कर

ली जाएं। उन्होंने कहा कि 'महादेवा महोत्सव धार्मिक आस्था और जनभावनाओं से जुड़ा आयोजन है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।'

उन्होंने तहसीलदार विपुल सिंह और लेखपाल संतोष कुमार को विशेष रूप से निर्देशित किया कि महोत्सव स्थल की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए।

इस मौके पर सीओ गरिमा पंत, कोतवाल अनिल कुमार पांडे, चौकी प्रभारी अभिनंदन पांडे, संतोष कुमार राय सहित कई पुलिसकर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि महादेवा महोत्सव को सफल और सुरक्षित बनाया जा सके।

पूर्व मंत्री अरविन्द सिंह गोप ने उदघाटन करते हुए मजार शरीफ पर पेश की चादर

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। कस्बा मसौली स्थित हजरत सैय्यद मीर शाह इस्माइली (रह0) की मजार शरीफ पर चल रहे तीन दिवसीय जलसे के प्रथम दिन पूर्व मंत्री अरविन्द सिंह गोप ने उदघाटन करते हुए मजार शरीफ पर चादर पेश की।

मजार शरीफ पर चादर पेश कर देश एव समाज में अमन चैन की दुआएं मांगते हुए पूर्व मंत्री अरविन्द सिंह गोप ने कहा कि मेले भारतीय संस्कृति और कौमी एकता का सन्देश देते है । जिसमें हर धर्म के लोग अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपनी भागीदारी निभाते है। सूफी सन्तो ने हमेशा समाज में एकता का संदेश दिया है। उनकी दुवाओं की बदौलत ही आज संसार चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेलो में सभी धर्मा

व समाज के लोग आपसी गिले शिकवे मिटाकर आपस में मिलते है। हम लोगो को सूफी सन्तो के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए उन्होने हम लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। सभी लोगों को ऐसे आयोजनों में आगे आना चाहिए। इस मौके पर पूर्व डीडीसी कृष्ण कुमार रावत ने मजार शरीफ पर चादर पेश कर अमन चैन एव खुशहाली की दुवा मांगी।

इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद, धीरेन्द्र वर्मा, सैय्यद फरहान वास्ती, पूर्व सदस्य जिला पंचायत शकील सिद्दीकी, मुईन प्रधान, हाजी मामा, डा0 इकबाल, लल्लू प्रधान , नौशाद राइन सहित तमाम जायरीन मौजूद रहे।

प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह की मौजूदगी में आयोजित थाना समाधान दिवस

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। नायब तहसीलदार रामनगर विजय प्रकाश तिवारी, नायब तहसीलदार नवाबगंज आशुतोष उपाध्याय एवं प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह की मौजूदगी में आयोजित थाना समाधान दिवस मे आधा दर्जन शिकायती पत्र आये अधिकारियों ने सभी मामलों में संबंधित विभागीय कर्मचारियों को स्थलीय जांच कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

ग्राम हसनपुर पहाड़ापुर निवासी हरिश्चंद्र व रमेश कुमार पुत्रगण स्व. गोबरे ने गांव के ही सियाराम पुत्र गोबरे तथा दुर्गेश पुत्र सियाराम पर जबरन भवन निर्माण कराने का आरोप लगाया। वहीं देवा के इब्राहिमपुर

निवासी प्रेम कुमारी ने फतेहपुर निवासी बुधराम व नन्दलाल पर उनके खेत में जबरन मेड़ बनाने की शिकायत दर्ज कराई। बादीपुरवा मजरे त्रिलोकपुर निवासी मिलन पुत्र रामफल, थाना फतेहपुर के ग्राम रालभारी निवासी रेशमा पत्नी मुन्नू, त्रिलोकपुर निवासी इरफान पुत्र स्व. मुन्नू, और केदार पुत्र स्व. बाबू ने भी अलग-अलग मामलों में भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायतें प्रस्तुत कीं। नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय, विजय प्रकाश तिवारी एवं प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह ने सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए राजस्व एव पुलिस टीम का गठन किया।

इस मौके पर अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सनत कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक शमशाद अली, उप निरीक्षक राहुल शर्मा, राजकरन सिंह, अभय गुप्ता, रमेश चंद्र, राजस्व निरीक्षक स्वामी नाथ सोनी सहित संबंधित लेखपाल व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।